



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2016/माघ 14, 1937

No. 45]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2016/MAGHA 14, 1937

वित्त मंत्रालय

(वार्षिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2016

फा. सं. 20/6/2015-एफ. टी. (भाग-7).— केंद्रीय सरकार, लोगों को निजी रूप से धारित स्वर्ण के स्टॉक का मुद्राकरण करने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराने की दृष्टि से, एतद्वारा 'स्वर्ण मुद्राकरण योजना - 2015' अधिसूचित करती है। इसमें 'नवीकृत स्वर्ण जमा योजना' और 'नवीकृत स्वर्ण धातु ऋण योजना' केंद्रीय बजट 2015-16 में की गई घोषणा के अनुसार शामिल है, जिन्हें एक साथ संबद्ध किया गया है और तदनुसार, स्वर्ण जमा योजना 1999 और स्वर्ण धातु ऋण योजना-1998 में निहित उपबंध, समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के अधीन, स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015 पर लागू होंगे।

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ - (1) इस योजना को स्वर्ण मुद्राकरण योजना - 2015 कहा जाएगा। इसमें 'नवीकृत स्वर्ण जमा योजना' और 'नवीकृत स्वर्ण धातु ऋण योजना' को एक साथ शामिल किया गया है।

(2) यह योजना इसके शुरू होने की तारीख से प्रभावी होगी।

2. परिभाषा - इस योजना में जब तक पाठ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "योजना" से स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015 अभिप्रेत है और इसमें 'नवीकृत स्वर्ण जमा योजना' और 'नवीकृत स्वर्ण धातु ऋण योजना' शामिल है;

(ख) "विनिर्दिष्ट बैंक" से ऐसा प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत विनियमित है, इसमें योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं;

(ग) "स्वर्ण जमा खाता" से इस योजना के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट बैंक में खोला गया और स्वर्ण के ग्रामों में मूल्यवर्गित खाता अभिप्रेत है;

(घ) "मध्यावधि सरकारी जमा" से किसी विनिर्दिष्ट बैंक में स्वर्ण मुद्रिकरण योजना के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार के खाते में पांच से सात वर्षों की मध्यावधि या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित ऐसी अवधि के लिए की गई स्वर्ण की जमा अभिप्रेत है;

(ङ.) "दीर्घावधि सरकारी जमा" से विनिर्दिष्ट बैंक में स्वर्ण मुद्रिकरण योजना के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार के खाते में बारह से पंद्रह वर्षों की दीर्घावधि या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित ऐसी अवधि के लिए की गई स्वर्ण की जमा अभिप्रेत है;

(च) "परिष्करणकार" से स्वर्ण मुद्रिकरण योजना के अंतर्गत, जमा और मोचन किए गए स्वर्ण को संभालने के प्रयोजन से, भारतीय मानक ब्यूरो से, अनुज्ञप्ति प्राप्त और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित परिष्करणकार अभिप्रेत हैं;

(छ) "संग्रहण और शुद्धता परीक्षण केंद्र" से संग्रहण और परख करने वाले ऐसे केंद्र अभिप्रेत हैं जिन्हें स्वर्ण मुद्रिकरण योजना के अंतर्गत जमा और मोचन किए गए स्वर्ण को संभालने के प्रयोजन से, भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है;

(ज) "अल्पावधि बैंक जमा" से किसी विनिर्दिष्ट बैंक में स्वर्ण मुद्रिकरण योजना के अंतर्गत एक से तीन वर्ष की अल्पावधि के लिए की गई स्वर्ण की जमा अभिप्रेत है।

3. इस योजना के प्रचालक - सभी विनिर्दिष्ट बैंक इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए पात्र होंगे।

4. स्वर्ण जमा करने के लिए पात्र व्यक्ति - (1) इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों सहित निवासी भारतीय, हिंदू अविभक्त कुटुम्ब, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूच्यूल फंड) विनियमन, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत म्यूच्यूल फंडों या एक्सचेंज कारोबारित फंडों सहित न्यास, धर्मार्थ संस्थाएं, फर्मों और कंपनियां जमा कर सकेंगी।

(2) इस योजना के अंतर्गत दो या अधिक पात्र जमाकर्ताओं की संयुक्त जमा की जा सकेगी और ऐसे मामले में जमा ऐसे जमाकर्ताओं के नाम पर खोले गए संयुक्त जमा खाते में जमा की जाएगी।

5. नवीकृत स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत स्वर्ण का संग्रहण, शुद्धता प्रमाणन और जमा - (1) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले परख और हॉलमार्किंग केंद्र इस योजना के प्रयोजन के लिए स्वर्ण की शुद्धता हेतु संग्रहण और शुद्धता परीक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे।

(2) किसी ग्राहक द्वारा जमा की जाने वाली स्वर्ण की न्यूनतम मात्रा 30 ग्राम होगी और स्वर्ण बुलियन या आभूषण के रूप में स्वीकार्य होगा।

6. स्वर्ण बचत खाता - ग्राहक यथाप्रयोज्य 'अपने ग्राहक को जाने' संबंधी मानकों के आधार पर, किसी भी समय स्वर्ण बचत खाता खोल सकेंगे और ऐसा खाता स्वर्ण के ग्रामों में मूल्यवर्गित किया जाएगा।

7. परिष्करणकारों को स्वर्ण का अंतरण - (1) संग्रहण और शुद्धता परीक्षण केंद्र परिष्करणकारों को स्वर्ण भेजेंगे और जब तक बैंक स्वयं स्वर्ण धारिता को तरजीह न दें, तब तक परिष्करणकार स्वर्ण को अपने भांडागारों में रखेंगे।

(2) परिष्करणकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए, बैंक उन्हें परस्पर निश्चित शुल्क अदा करेंगे और ग्राहकों पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

8. विधिक करार - बैंक ऐसे परिष्करणकारों और संग्रहण तथा शुद्धता परीक्षण केंद्रों के साथ विधिक करार (त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय) कर सकेंगे, जिनका चयन उनके द्वारा योजना में उनका भागीदार बनने के लिए किया जाए।

9. समयावधि: नवीकृत योजना के अंतर्गत जमा एक से तीन वर्ष की अल्पावधि, पांच से सात वर्ष की मध्यावधि और बारह से पंद्रह वर्ष की दीर्घावधि (या समय-समय पर यथा निर्धारित) के लिए की जा सकती है और इन सभी विकल्पों में लॉक-इन

अवधि का बहिष्करण सावधि जमा पर लागू होने वाले नियमों के समान ही अनुमत होगा और समय-पूर्व परिपक्व मोचन (आंशिक आहरण सहित) पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

10. ब्याज दर - (1) अल्पावधि के लिए की गई जमाओं के लिए संदेय ब्याज दर की राशि प्रचलित अंतरराष्ट्रीय पट्टा दरों, अन्य लागतों और बाजार परिस्थितियों के आधार पर बैंकों द्वारा विनिश्चित की जाएगी और स्वर्ण के ग्रामों में मूल्यवर्गित की जाएगी।

(2) मध्यावधि और दीर्घावधि जमाओं के लिए, ब्याज दर (और बैंक को उनकी सेवाओं के लिए अदा किए जाना वाला शुल्क) सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाएगा और मध्यावधि और दीर्घावधि जमाओं के लिए ब्याज दर, जमा स्वर्ण के मूल्य के आधार पर, भारतीय रुपए में मूल्यवर्गित और संदेय होगी।

11. मोचन - (1) अल्पावधि जमाओं के लिए, ग्राहक के पास मूल जमा और अर्जित ब्याज का मोचन नकद या स्वर्ण में करने का विकल्प होगा, जिसका चयन स्वर्ण जमा करते समय किया जाना होगा।

(2) यदि ग्राहक विकल्प में बदलाव करना चाहे, तो यह बैंक के विवेक पर अनुमत होगा।

(3) मध्यावधि और दीर्घावधि जमाओं के लिए, मोचन केवल नकद में होगा। यह मोचन के समय प्रचलित कीमतों पर सोने के मूल्य के समतुल्य रुपए में होगा।

12. उपयोगिता - जमा स्वर्ण का उपयोग निम्नानुसार तरीके से किया जाएगा, अर्थात :-

(1) मध्यावधि और दीर्घावधि जमा के अंतर्गत:

(क) नीलामी: जमा स्वर्ण की भारतीय रिजर्व बैंक या खनिज और धातु व्यापार निगम अथवा सरकार की किसी अन्य प्राधिकृत एजेंसी द्वारा यथा शीघ्र नीलामी की जाएगी और प्राप्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार सरकारी उधारों की एवज में करेगी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडार की पुनर्पूर्ति: जमा स्वर्ण भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडार में जमा किया जा सकेगा।

(ग) सिक्के: बैंक इस प्रकार जुटाए गए स्वर्ण को धातु और खनिज कारोबार निगम को भारतीय स्वर्ण सिक्के बनाने के लिए उपलब्ध करा सकेंगे।

(घ) आभूषणकारों को उधार: बैंक स्वर्ण धातु ऋण योजना के अंतर्गत आभूषणकारों को उधार दे सकेंगे।

(2) अल्पावधि जमा के अंतर्गत:

(क) सिक्के: बैंक इस प्रकार जुटाए गए स्वर्ण को धातु और खनिज व्यापार निगम को, भारतीय स्वर्ण सिक्के बनाने के लिए उपलब्ध करा सकेंगे।

(ख) आभूषणकारों को उधार: बैंक स्वर्ण धातु ऋण योजना के अंतर्गत आभूषणकारों को उधार दे सकेंगे।

13. कर छूट - कर छूटें, जो स्वर्ण जमा योजना, 1999 के अंतर्गत उपलब्ध हैं, स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015 के अंतर्गत, जैसा लागू हो, ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

14. स्वर्ण आरक्षित निधि - सरकार के लिए वर्तमान उधार लागत और मध्यम या दीर्घावधि जमा के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज दर के बीच का अंतर स्वर्ण आरक्षित निधि में जमा कर दिया जाएगा, जिसका अनुरक्षण सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक करेगा।

15. योजना की अवधि - यह योजना आगामी नोटिस तक प्रचालनरत रहेगी।

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2016

F. No. 20/6/2015-FT(Pt.-7).—The Central Government, with a view to provide different options to the people to monetize the privately held stock of the gold, hereby notifies the ‘Gold Monetisation Scheme-2015’ comprising the ‘Revamped Gold Deposit Scheme’ and the ‘Revamped Gold Metal Loan Scheme’, which are hereby linked together as announced in the Union Budget 2015-16 and accordingly, the Provisions contained in the Gold Deposit Scheme 1999 and the Gold Metal Loan Scheme-1998 shall be applicable to Gold Monetisation Scheme-2015, subject to amendments from time to time.

1. Short title and commencement – (1) This scheme shall be called the Gold Monetisation Scheme -2015 comprising the ‘Revamped Gold Deposit Scheme’ and the ‘Revamped Gold Metal Loan Scheme’ linked together.

(2) It shall come into force from the date of launch of the Scheme.

2. Definition - In this scheme unless the context otherwise requires —

(a) “Scheme” means the Gold Monetization Scheme, 2015 and includes the Revamped Gold Deposit Scheme and the Revamped Gold Metal Loan Scheme;

(b) “Designated bank” means each Scheduled Commercial Bank which is included in the second schedule of Reserve Bank Act, 1934 and regulated under Banking Regulation Act, 1949, excluding Regional Rural Banks that decide to implement the Scheme;

(c) “Gold Deposit Account” means an account opened with a designated bank under the scheme and denominated in grams of gold;

(d) “Medium Term Government Deposit” means the deposit of gold made under the Gold Monetisation Scheme with a designated bank in the account of the Central Government for a medium term period of five to seven years or for such period as may be decided from time to time by the Central Government;

(e) “Long Term Government Deposit” means the deposit of gold made under the Gold Monetisation Scheme with a designated bank in the account of the Central Government for a long term period of twelve to fifteen years or for such period as may be decided from time to time by the Central Government;

(f) “Refiners” means the refiners licensed by Bureau of Indian Standards and notified by the Central Government for the purpose of handling gold deposited and redeemed under Gold Monetisation Scheme;

(g) “Collection and Purity Testing Centre” means the collection and assaying centres certified by the Bureau of Indian Standards and notified by the Central Government for the purpose of handling gold deposited and redeemed under Gold Monetisation Scheme;

(h) “Short Term Bank Deposit” means the deposit of gold made under the Gold Monetisation Scheme with a designated bank for a short term period of one to three years.

3. Who can operate the scheme - All designated banks will be eligible to implement the Scheme.

4. Who are eligible to make a deposit – (1) Resident Indians including Individuals, Hindu Undivided Families, Trusts including Mutual Funds or Exchange Traded Funds which are registered under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations, 1996, charitable institutions, Firms and Companies, may make deposits under the scheme.

(2) Joint deposits of two or more eligible depositors may be made under the scheme and the deposit in such case shall be credited to the joint deposit account opened in the name of such depositors.

5. Collection, Purity Verification and Deposit of Gold under the Revamped Gold Deposit Scheme – (1) Assaying and Hallmarking Centres which meet the criteria as specified by the Bureau of Indian Standards shall act as Collection and Purity Testing Centres for purity of gold for the purpose of this scheme.

(2) The minimum quantity of gold that a customer may deposit shall be 30 grams and the Gold may be in the form of bullion or jewellery.

6. Gold Savings Account - A Gold Savings Account shall be opened by customers at any time, with Know Your Customer norms, as applicable and such account shall be denominated in grams of gold.

7. Transfer of Gold to the Refiners – (1) The Collection and purity testing centres shall send the gold to the refiners and the refiners shall keep the gold in their ware-houses, unless the banks prefer to hold it themselves.

(2) For the services provided by the refiners, they shall be paid a fee by the banks, as decided by them, mutually and the customer shall not be charged.

8. Legal Agreement - The banks may enter into a Legal Agreement (tripartite/ bipartite) with refiners and Collection and Purity Testing Centres, that are selected by them to be their partners in the scheme.

9. Tenure: The deposits under the revamped scheme can be made for a short-term period of one to three years, a medium-term period of five to seven years and a long-term period of twelve to fifteen years (or as decided from time to time), and breaking of lock-in period shall be allowed in any of the options in the same manner as fixed deposit and a penalty on premature redemption (including part withdrawal) may be imposed.

10. Interest rate – (1) The amount of interest rate payable for deposits made for the short-term period shall be decided by the banks on the basis of the prevailing international lease rates, other costs and market conditions and shall be denominated in grams of gold.

(2) For the medium and long-term deposits, the rate of interest (and fees to be paid to the bank for their services) shall be decided by the government from time to time and the interest rate for the medium and long-term deposits shall be denominated and payable in rupees, based on the value of gold deposited.

11. Redemption – (1) For short-term deposits, the customer shall have the option of redemption, for the principal deposit and interest earned, either in cash or in gold, which shall have to be exercised at the time of making the deposit.

(2) In case the customer intends to change the option, it shall be allowed at the bank's discretion.

(3) For medium and long-term deposits, redemption shall be only in cash, in rupees equivalent of the weight of the deposited gold at the prices prevailing at the time of redemption.

12. Utilization - The deposited gold shall be utilized in the following manner, namely:-

(1) Under Medium and Long-Term Deposit:

(a) Auctioning: The gold deposited may be auctioned by Reserve Bank of India or Metals and Minerals Trading Corporation or any other authorized agency by the Government, at the earliest and amount realized will be used by Government of India in lieu of government borrowing.

(b) Replenishment of Reserve Bank India's Gold Reserves: The deposited gold may be credited to Reserve Bank India's gold reserves.

(c) Coins: Banks may provide the mobilized gold to Minerals and Metals Trading Corporation for minting the Indian Gold Coins.

(d) Lending to jewellers: Banks may lend to jewellers under the Gold Metal Loan Scheme.

(2) Under Short-Term Deposit:

(a) Coins: Banks may provide the mobilized gold to Metals and Minerals Trading Corporation for minting the Indian Gold Coins.

(b) Lending to jewellers: Banks may lend to jewellers under the Gold Metal Loan Scheme.

13. Tax Exemption - Tax exemptions, same as those available under Gold Deposit Scheme would be made available to the customers, in the Gold Monetisation Scheme-2015, as applicable.

14. Gold Reserve Fund - The difference between the current borrowing cost for the Government and the interest rate paid by the Government under the medium or long term deposit shall be credited to the Gold Reserve Fund which shall be maintained by Reserve Bank of India on behalf of government.

15. Period of the Scheme - The scheme shall remain in operation until further notice.

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.